

न्यायालय कलक्टर, एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ (राज.)  
पीठासीन अधिकारी के. के. शर्मा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 47/2019 (रे.वि.)  
पंजीयन दिनांक 03.09.2019  
G.C.M.S. NO.: 2019/00135

ए. यु. स्माल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (जो पूर्व में ए. यु. फाईनेन्सियर्स इण्डिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) जिसका मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19 ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर (राज.) पिन नम्बर 302001 में स्थित व कार्यरत है जरिये प्राधिकृत अधिकारी

-प्रार्थी

बनाम

- 1-श्री राधेश्याम रूपलाल लौहार पिता रूपलाल हजारी लौहार, 6 निवासी देवीपुरा, ई-टंकी के पास, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) पिन नम्बर 312203 एट आलसो राधेश्याम रूपलाल लौहार, पट्टा नम्बर 36, संकल्प नम्बर 01, मिसल नम्बर 93, ग्राम पंचायत सोमी, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
- 2-श्रीमति मांगी बाई लौहार पत्नि राधेश्याम रूपलाल लौहार मृतक के बजाए:-  
2/1-रेखा पुत्री राधेश्याम उम्र 16 वर्ष नाबालिग जरिये बवलायत प्राकृतिक संरक्षक पिता राधेश्याम जी लौहार निवासी 74 देवीपुरा, ई-टंकी के पास, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
- 3-श्री निर्मल कुमार जैन पिता गोविन्दसिंह निवासी 26 महेश नगर, चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002


उपस्थिति : 1- श्री किशन सिंह गाडन, अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश

दिनांक 29.12.2020



प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रुपये 4,00,000/- रु. की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। ऋण राशि के पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण द्वारा अपनी निम्न सम्पत्ति को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा बकाया राशि जमा नहीं कराये जाने से यह आवेदन प्रस्तुत किया गया।

  
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
चित्तौड़गढ़

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को रजिस्टर्ड ए. डी. के माध्यम से सूचना पत्र प्रेषित किये गये। विपक्षी संख्या 1 व 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। विपक्षी संख्या 2 की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर उसके वारिसान को रेकॉर्ड पर लिया जाकर उसे सूचना पत्र जारी किया गया। विपक्षी संख्या 2 के वारिसान भी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। बहस प्रकरण अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वित्तीय संस्था एक निगमित निकाय है, जो अपनी शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग व्यवसाय करती है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने इस शाखा से अप्रार्थीगण को उक्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी जिसके तहत रहन की गई जायदाद का विवरण निम्न है:-

राधेश्याम रूपलाल लौहार पिता रूपलाल हजारी लौहार, 6 निवासी देवीपुरा, ई-टंकी के पास, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज) पिन नम्बर 312203 एट आलसो राधेश्याम रूपलाल लौहार, पट्ट नम्बर 36, संकल्प नम्बर 01, मिसल नम्बर 93, ग्राम पंचायत सोमी, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज) पिन कोड नम्बर 312203 पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं बांघा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका कुलिया माप 1343 स्वचायर फीट है।

चर्चुसीमा:-

पूर्व :- भगवान लौहार की सम्पत्ति

उत्तर :- नारू, रामा अहीर की सम्पत्ति

पश्चिम :- हीरा जीवा चमार की सम्पत्ति

दक्षिण :- सड़क

उक्त सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन रख कर ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण व ब्याज की राशि नियमित भुगतान नहीं करने पर, प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जिससे अप्रार्थीगण के जिम्मे दिनांक 27.12.2018 तक राशि रूपये 3,42,926/- रूपये तथा ब्याज व अन्य चार्जेज देय निकलते है। उक्त राशि का भुगतान नहीं करने से अप्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा बतौर जमानत प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा जरिए पुलिस इमदाद प्रार्थी वित्तीय संस्था को दिलाया जावे।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को ऋण उपलब्ध कराये जाने से इस राशि के पुनर्भरण हेतु बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद अप्रार्थीगण ने वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन रखी है। वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी उपरोक्त बकाया राशि जमा नहीं कराई गयी है। द सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्वोरिटी इन्टरेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002 की धारा 14 में सर्व प्रथम उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी वित्तीय संस्था के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः ऋणी द्वारा वित्तीय संस्था में रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को दिलाया जाना उचित है।



कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
चित्तौड़गढ़



अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था के पक्ष में रखी गयी पैरा संख्या 3 में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था प्रतिनिधि को जरिये पुलिस संभलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'



(के. के. शर्मा)

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
चिचौइगढ